



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263054
CG-DL-E-13052025-263054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947

No. 337]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

नं.01/Aadhaar/DBT/2020-EMR-1.—जबकि, आधार का उपयोग सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके लाभार्थियों को उनके अधिकारों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

और जबकि, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (इसके बाद विभाग के रूप में संदर्भित), अपनी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास स्कीम (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) के अधीन डॉक्टरल और पोस्टडॉक्टरल फैलोशिप योजना का संचालन कर रहा है, जिसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली (इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और जबकि, इस योजना के अधीन, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के रिसर्च अध्येताओं (फैलो) (इसके बाद लाभार्थी के रूप में संदर्भित) को वर्तमान स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार मासिक वृत्ति (इसके बाद लाभ के रूप में संदर्भित) दी जाती है;

और जबकि, पूर्वोक्त योजना में भारत की समेकित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्;

1. (1) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र नहीं है तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि, आधार संख्या प्राप्त होने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही योजना के अधीन लाभ दिया जाएगा, अर्थात्:

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

- (i) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली पास बुक; या
- (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) राशन कार्ड; या
- (v) मतदाता पहचान पत्र; या
- (vi) मनरेगा कार्ड, या
- (vii) किसान फोटो पासबुक; या
- (viii) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59); के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, या
- (ix) आधिकारिक लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या
- (x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस योजना के अधीन लाभार्थियों को सुगमता पूर्वक लाभ प्रदान करने हेतु विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है तो, निम्नलिखित उपचारात्मक प्रक्रिया अपनायी जाएगी, अर्थात्: -

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को अपनाया जाएगा, अतः विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या फेस ऑथेंटिकेशन का प्रावधान कराएगा ताकि लाभ निर्बाध रूप से दिया जा सके।

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल न होने की स्थिति में, जहां भी संभव और अनुमेय हो, आधार द्वारा वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण का प्रावधान होगा।

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अधीन मूल आधार पत्र जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पॉंस (क्यू आर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, और क्यू आर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अधीन कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या D-26011/04/2017-DBT में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करेगा। (<http://dbtbharat.gov.in/> पर उपलब्ध)

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

महेन्द्र कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./69/2025-26]

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH, NEW DELHI

New Delhi, the 17th March, 2025

No.01/Aadhaar/DBT/2020-EMR-1.—WHEREAS, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND WHEREAS, the Council of Scientific and Industrial Research, Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India (hereinafter referred to as the Department), is administering the Doctoral and Postdoctoral Fellowship Scheme under its National Science and Technology Human Resource Development Scheme (hereinafter referred to as the Scheme), which is being implemented through the Council of Scientific and Industrial Research New Delhi (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

AND WHEREAS, under the Scheme, the monthly stipend (hereinafter referred to as the benefit) is given to the Council of Scientific and Industrial Research Fellows (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND WHEREAS, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby notifies the following, namely;

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) (website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Register themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely;

- (a) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:

- (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
- (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Ration Card; or
- (v) Voter Identity Card; or
- (vi) MGNREGA card, or
- (vii) Kisan Photo passbook; or
- (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; or
- (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:
 - (a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
 - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated 19th December, 2017. (Available on <http://dbtbharat.gov.in/>)
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories.

MAHENDRA KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./69/2025-26]